Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 3 | MARCH 2023

भारत में वित्तीय साक्षरताः दशा और दिशा

डॉ. प्रेम परिहार [1]

[1] सहायक आचार्य, ईएएफएम, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, राजस्थान

ABSTRACT:

वित्तीय साक्षरता का सीधा सा अर्थ है धन या मुद्रा के उपयोग करने के सही तरीके को समझने एवं समझाने की क्षमता का होना। इसका अभिप्राय यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या कौशल होते ह जिनके माध्यम से वह सोच समझ कर धन या मुद्रा से संबंधित प्रभावशाली निर्णय ले सकता है। वित्तीय साक्षरता वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की माँग का निर्माण करती है। वित्तीय साक्षरता प्रभावी पूँजी निर्माण का द्वार है जो रोजगार एवं गरीबी निवारण में सहयोग प्रदान करतो है। ग्लोबल फाइनेंशिएल लिटरेसी एक्सीलेंसी सेंटर के अनुसार भारत में वित्तीय साक्षरता की दर व्यस्क आबादी में मात्र 24 प्रतिशत ही है जोकि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यह अंतर ग्रामीण और शहरी भारत में अधिक है। महानगरों में वित्तीय साक्षरता अधिक जबकि गाँवों एवं पिछड़े राज्यों में कम है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रमां का संचालन करती है। इसके लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता का तकनीकी समूह एवं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् समन्वित रूप से काम करती है। वित्तीय साक्षरता योजना चालू की गई है। इसके माध्यम से वित्तीय साक्षरता की दर को बढ़ाया जा सके और आम नागरिकों को वित्तीय शिक्षा दी जा सके क्योंकि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए यह मुख्य घटक है। प्रस्तुत लेख में भारत में वित्तीय साक्षरताः दशा और दिशा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

KEYWORDS:

वित्तीय साक्षरता, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय स्थिरता और विकास परिशद्, वित्तीय साक्षरता योजना

भाोध–पत्र

वित्तीय साक्षरता का सीधा सा अर्थ है धन या मुद्रा के उपयोग करने के सही तरीके को समझने एवं समझाने की क्षमता का होना। इसका अभिप्राय यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या कौशल होते है जिनके माध्यम से वह सोच समझ कर धन या मुद्रा से संबंधित प्रभावशाली निर्णय ले सकता है। वित्तीय साक्षरता वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की माँग का निर्माण करती है। यह ज्ञान व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रभावी वित्तीय नियोजन करता है, ऋण का उचित प्रबंधन करता है, ब्याज की गणना आसानी से कर लेता है और वह धन के समय मूल्य को जानता है तो यह माना जाता है कि वह वित्तीय रूप से साक्षर है। विस्तृत अर्थ में इसमें बजट बनाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और सेवा निवृति की सही योजनाओं कर निर्माण करना भी इसमें शामिल है। इससे व्यक्ति को बैंकों द्वारा प्रदत्त उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकताओं तथा लाभों की जानकारी मिलती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन को गति मिलती है। यह सत्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को किसी न किसी रूप में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता रहती है। वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य सुलभ वित्तीय साधन एवं साक्षरता के माध्यम से वित्तीय साक्षरता समावेशन को आसान बनाना ळें

अध्ययन की आवश्यकता के कारणः–

1. वित्तीय साक्षरता क्या हैं? को जानना।
2. भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति को जानना।
3. वित्तीय साक्षरता में सहयोग करने वाली संस्थाओं को जानना।

भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। यह एक गैर–लाभकारी कंपनी है जोकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई है। इस कंपनी को प्रमुख वित्तीय नियामकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए द्वारा सहयोग दिया जाता है। यह कंपनी वित्तीय साक्षरता स्तर का पता लगाने के लिए सर्वे करती है एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह विद्यालयो एवं महाविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता प्रदान करती है। वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम कनाडा, जापान, सऊदी अरब, अमेरिका आदि देशों में भी संचालित किए जाते ह। यद्यपि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने सामान्य वित्तीय साक्षरता सिद्धान्त के विकास के माध्यम से वित्तीय शिक्षा और साक्षरता मानकों में सुधार के तरीके प्रदान करने के लिए वर्ष 2003 में एक परियोजना की शुरूआत की थी। मार्च 2008 से वित्तीय शिक्षा के लिए अन्तराष्ट्रीय गेटवे प्रारम्भ किया है। इसका कार्य विश्व में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों की सूचना एवं अनुसंधान का विकास करना है।

भाोध समीक्षाः–

मीणा राजगोपाल एवं भादीद यशोदा 2012 ने **वित्तीय साक्षरता के लिए राश्ट्रीय रणनीति** में लिखा है कि भारत एक विशाल राष्ट्र है तो इसे भी अन्य राष्ट्रों की भाति वित्तीय साक्षरता के लिए एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय नीति अपनाने की आवश्यकता है। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थाए, शिक्षाविद् और अन्य सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। एक विशाल शिक्षा अभियान के माध्यम से लोगों को वित्तीय सेवाओं के माध्यम से धन के अधिक कारगर प्रबंधन करने में मदद की जा सकती है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार वित्तीय साक्षरता वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, काशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहार का संयुक्त एवं समग्र रूप है। जिसकी सहायता से वित्तीय फसले लिए जा सके और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से लोग वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते ह। विश्व में चैक गणराज्य, नीदरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन जैस देश वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी कर चुके है।

स्मृति कम्बोज 2014 ने शोध–पत्र **करंट सेनेरियो ऑफ फाइनेंशिएल लिटरेसी इन इण्डिया** में बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। वह स्वयं सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा दे रहा है। भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए अधिक शोधपरक कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस हेतु वित्तीय साक्षरता एवं साख काउंसिल 2009 की स्थापना की है। इसके बाद अनेक बैंकों के द्वारा वित्तीय साक्षरता के कार्य में सहयोग प्रदान किया है जिनमें बैंक ऑफ इण्डिया का अभय, आईसीआईसीआई बैंक का दिशा, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा महाराष्ट्र में परामर्श केंद्र खोलना प्रमुख है। ये सभी ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी प्रदान करते हैं।

अजीज अब्दुल एन. पी. एवं अख्तर जावेद एस. एम. 2021 ने लेख **डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशिएल लिटरेसी इन रूरल इण्डिया** में बताया है कि वित्तीय साक्षरता जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा स्तर आदि सभी आर्थिक चरों के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण कौशल है लेकिन इसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में में बहुत कम हुआ है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय सेवा प्रदाता संस्थानों के द्वारा वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। परन्तु आज सभी वित्तीय संस्थान वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जबकि उन्हें वित्तीय साक्षरता पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वित्तीय साक्षरता ही वित्तीय समावेशन को आसान एवं अधिक बनाती है।

वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता के कारणः–

1. धन में धोखाधड़ी से बचाव के लिए।
2. सही वित्तीय प्रबंधन के लिए।
3. आय सृजन एवं पूजी निर्माण की दर में वृद्धि के लिए।
4. आय–व्यय में नियंत्रण के लिए।
5. भविष्य की सुरक्षा के लिए बचतों का निवेश करने को सही प्रक्रिया जानने के लिए।

6. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के लिए।
7. आय के उत्तम स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
8. बेहतर एवं लाभकारी विकल्पों के चयन के लिए।

राश्ट्रीय रणनीति के प्रमुख लक्ष्यः–

1. वित्तीय सेवाओं, विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं उनकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना एवं शिक्षित करना।
2. जानकारी को व्यवहार में बदलने की प्रवृति को विकसित करना।
3. वित्तीय सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय संदेशों का प्रचार–प्रसार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष यह सप्ताह 14–18 फरवरी 2022 को मनाया गया। इसकी विषय–वस्तु **डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ** रही। यह विषय वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य नीति 2020–2025 के उद्देश्यों में से एक है। इसके तहत् डिजिटल लनदेन की सुविधाए, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और ग्राहकों के संरक्षण के बारे में बताया गया। इसी वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका का तीसरा संस्करण भी जारी किया। इसके अतिरिक्त बेसिक फाइनेंशिएल लिटरेसी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और गाइंग डिजिटल पर आडियो विज़ुअल सेवा भी है जो वित्तीय साक्षरता के संदेश देती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने "वित्तीय शिक्षा रिपोर्ट 2020–25 के लिए राष्ट्रीय नीति" नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि देश में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 C पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 5 C है– Content सामग्री, Capacity क्षमता, Community समुदाय, Communication संचार एवं Collaboration सहयोग प्रमुख है।

इसके लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता का तकनीकी समूह एवं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (2012) समन्वित रूप से काम करती है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता योजना भी चला रखी है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, महिलाओं, लक्षित समूहों, गरीबों, ग्रामीणों आदि के लिए वित्तीय एवं बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

ग्लोबल फाइनेंशिएल लिटरेसी एक्सीलेंसी सेंटर के अनुसार भारत में वित्तीय साक्षरता की दर व्यस्क आबादी में मात्र 24 प्रतिशत ही है जोकि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। महानगरों में वित्तीय साक्षरता अधिक एवं गरीब और पिछड़े राज्यों में कम पाई जाती है। ऐसी ही रिपोर्ट भारतीय वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन सर्वे रिपोर्ट 2019 में बताया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय साक्षरता की दर 27 प्रतिशत है जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 33 प्रतिशत है। महिलाओं में यह दर 21 प्रतिशत और पुरूषों में 29 प्रतिशत है। आयु वर्ग के आधार पर विश्लेषण करने पर तो 18–29 वर्ष के आयु वर्ग में 30 प्रतिशत, 30–49 वर्ष के आयु वर्ग में 27 प्रतिशत, 50–59 वर्ष के आयु वर्ग में 25 प्रतिशत, 60–69 वर्ष के आयु वर्ग में 23 प्रतिशत, 70–80 वर्ष के आयु वर्ग में 27 प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर है। जबकि राजस्थान में यह दर मात्र 20 प्रतिशत ही है। इस दर में अब काफी बदलाव हुआ है जैसा कि तालिका में स्पष्ट है–

विवरण	वर्ष 2013 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	वर्ष 2019 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	विवरण	वर्ष 2013 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में	वर्ष 2019 में वित्तीय साक्षरता की दर प्रतिशत में
सामान्य जाति	24	29	पुरूष	23	29
अन्य पिछड़ वर्ग	17	26	महिला	16	21
अनुसूचित जाति	14	25	ग्रामीण	15	24
अनुसूचित जन जाति	15	27	शहरी	25	33

यह सत्य है कि वित्तीय साक्षरता प्रभावी पूँजी निर्माण का द्वार है जो श्रम शक्ति को प्रभावित कर कौशल में विकास करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं गरीबी निवारण में सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय गतिविधियों की जागरूकता में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को इस प्रकार लागू करने का प्रयास करना चाहिए कि कम पढ़े–लिखे एवं साक्षर भी आसानी से समझ सके। वित्तीय साक्षरता में बुद्धिमानी से व्यय, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। महिलाओं को अधिक जागरूक करना आवश्यक है। भारत जैसे देश में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय साक्षर होना अति आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, वित्तीय संस्थानों का सक्रिय योगदान, वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच होना भी आवश्यक है।

REFERENCES

1. मीणा राजगोपाल एवं शदीद यशोदा, वित्तीय साक्षरता के लिए राष्ट्रीय रणनीति, पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई, भारत सरकार, 18 जुलाई 2012
2. स्मृति कम्बोज, करंट सेनेरियो ऑफ फाइनेंशिएल लिटरेसी इन इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरपेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, वाल्यूम 1, इश्यू 1, पृष्ठ संख्या 61–68, 2014
3. अजीज अब्दुल एन. पी. एवं अख्तर जावेद एस. एम., डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशिएल लिटरेसी इन रूरल इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशिएल इंजीनियरिंग, वाल्यूम 8, इश्यू 2, पृष्ठ संख्या 2150009.1–2150009.17 2021
4. वित्तीय साक्षरता गाइड, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, भारत सरकार, जनवरी 2013, पृष्ट संख्या 1–36
5. प्रेस प्रकाशनी, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, भारत सरकार, 2021–22 / 1705
6. माइकल एवं अन्य, स्कूल ऑफ स्टडी एण्ड फाइनेंशिएल लिटरेसी, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स एज्यूकेशन रिसर्च, 11(3), पृष्ट संख्या 29–37
7. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद रिपोर्ट 2015
8. भारत में वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019